

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 नवम्बर 2014—अग्रहायण 7, शक 1936

### विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-01/2014/1-15.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री कृष्ण चंद्र यादव, भा.व.से. (1984), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्री राजेन्द्र कुमार डे, भा.व.से. (1985), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2014

क्रमांक ई-1-04-2014/1/2.—राज्य शासन, एतद्वारा डॉ. कमलप्रीत सिंह, भा.प्र.से. (2002), संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, मंत्रालय के पद पर पदस्थ करता है।

नया रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2014

क्रमांक ई-1-04-2014/1/2.—राज्य शासन, एतद्वारा डॉ. व.मलप्रीत सिंह, भा.प्र.से. (2002), संयुक्त सचिव, मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ करता है तथा इसके साथ-साथ संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है।

2. श्री प्रसन्ना आर., भा.प्र.से. (2004), संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग तथा संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़ के पद पर पदस्थ करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विवेक ढांड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2014

क्रमांक ई 7-10/2014/1/2.—राज्य शासन, एतद्वारा श्री जगदीश सोनकर भा.प्र.से., सहायक कलेक्टर, कांकेर को दिनांक 25-09-2014 से दिनांक 04-10-2014 तक (10 दिवस) लघुकृत अवकाश (कार्योत्तर) स्वीकृत किया जाता है। साथ ही दिनांक 05, 06 अक्टूबर, 2014 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है।

2. अवकाश काल में श्री सोनकर, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे।
3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जगदीश सोनकर, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

नया रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2014

क्रमांक ई 7-08/2013/1/2.—राज्य शासन, एतद्वारा श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा, तत्कालीन सहायक कलेक्टर, राय को दिनांक 27-06-2013 से दिनांक 12-07-2013 तक (16 दिवस) लघुकृत अवकाश (कार्योत्तर) स्वीकृत किया जाता है। साथ ही दिनांक 13 एवं 14 जुलाई, 2014 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है।

2. अवकाश काल में श्री मीणा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे।
3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मीणा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुकुन्द राव अभिये, अवर सचिव.

## आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2014

क्रमांक एफ 7-31/2014/32.—संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा कोरबा विकास योजना के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार नगर पालिका निगम, कोरबा द्वारा 50 एकड़ भूमि में स्टेडियम का निर्माण किया जा चुका है। स्टेडियम के अलावा किसी भी प्रकार के निस्तार की आवश्यकता न होने के कारण अतिरिक्त अन्य निजी भूमि की आवश्यकता नहीं है। निजी भूमि ग्राम कोरबा, प.ह.नं. 09 स्थित भूमि खसरा क्रमांक 175/1, 172/2, 175/3, 175/13, 175/5, 175/11, 175/4 का भाग, 3/1झ, 3/1ज, 3/1प, 3/1घ/2, 172, 171 का भाग, 170 का भाग, 165 का भाग, 668, 163, 164 3/1त का भाग, 3/4छ, 3/4च, 3/4ज, 3/4झ, 3/4ग, 3/4ख, कुल रकबा 12.232 हेक्टेयर लगभग स्टेडियम हेतु आरक्षित है, से प्रभावित होने के कारण संशोधित किया जाना आवश्यक है।

2. अतः राज्य शासन, एतद्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 35(2) के प्रावधानों के अंतर्गत यह समाधान होने के पश्चात् कि कोरबा विकास योजना में वर्णित ग्राम कोरबा, प.ह.नं. 09 स्थित भूमि खसरा क्रमांक 175/1, 172/2, 175/3, 175/13, 175/5, 175/11, 175/4 का भाग, 3/1झ, 3/1ज, 3/1प, 3/1घ/2, 172, 171 का भाग, 170 का भाग, 165 का भाग, 668, 163, 164 3/1 त का भाग, 3/4छ, 3/4च, 3/4ज, 3/4झ, 3/4ग, 3/4ख कुल रकबा 12.232 हेक्टेयर लगभग स्टेडियम हेतु आरक्षित भूमि को कोरबा विकास योजना में स्टेडियम से निकाल देने जाने की मंजूरी देता है।

3. इस आदेश में जारी होने के दिनांक से प्रश्नाधीन भूमि कोरबा विकास योजना में दर्शित आरक्षण से निर्मुक्त हुई समझी जावेगी, और वह पार्श्वस्थ भूमि के मामले में सुसंगत योजना के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय विकास के प्रयोजन के लिए स्वामी को उपलब्ध हो जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव।

### राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 14 नवम्बर 2014

क्रमांक/8027/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	मगरधोखरा प. ह. नं. 06	0.279	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव (छ.ग.)	बनियाटोला-मगरधोखरा मार्ग पर स्थित झूरा नदी पर उच्च स्तरीय पुल मय पहुंच मार्ग हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ एवं  
पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व विभाग

मुंगेली, दिनांक 17 जुलाई 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-वर्ष 2012-13—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन--

- (क) जिला-मुंगेली  
(ख) तहसील-पथरिया  
(ग) नगर/ग्राम-मर्कोना  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.46 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
229	0.38
227/3	0.60
225/2	0.11
224/1	0.37
224/2	0.50
224/3	0.50
योग	6
	2.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मर्कोना एनीकट निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पथरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय अलंग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं  
पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 11 नवम्बर 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2013-14—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़  
(ख) तहसील-सारंगढ़  
(ग) नगर/ग्राम-नावापारा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.174 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
163/3	0.121
288, 291, 296	0.208
165	0.045
269/2	0.063
179/3	0.026
182/1	0.029
186/6	0.010
277	0.082
270/2, 271/2	0.170
273/2	0.094
302/1	0.167
77/2	0.090
181/2	0.270
278/1	0.040
287/1	0.047
297/3	0.037
299/2	0.210
175/2, 176/2	0.020
282	0.097
285/2	0.080
180	0.053

(1)	(2)	(1)	(2)
182/2	0.020	182/2क	0.048
182/4	0.020	182/5	0.010
268/2	0.162	268/1ख	0.023
280/2, 281/2	0.077	273/1	0.073
287/2	0.064	280, 281/3	0.077
302	0.191	275	0.084
120	0.283	178	0.158
276	0.072	123/1	0.228
278/3	0.005	278/2	0.027
267/2	0.061	285/1	0.080
297/4	0.032	297/5	0.084
164	0.283		
175/1, 176/1	0.192	योग	79 8.174
289/1	0.231		
269/3	0.069		
300, 301	0.502		
182/3ख	0.040		
269/4	0.032		
268/3	0.004		
266, 271	0.125		
267/1	0.036		
71/1	0.318		
121	0.198		
123/2	0.076		
279	0.065		
297/1	0.030		
298/2	0.087		
183	0.160		
175/3, 176/3	0.020		
167	0.119		
179/1	0.026		
284/1	0.039		
284/2	0.073		
268/1क	0.022		
270, 271	0.170		
280, 281/4	0.026		
274	0.066		
299/1	0.231		
122	0.672		
98/11	0.090		
298/1	0.043		
297/2	0.037		
298/4	0.044		
290	0.134		
280/1, 281/1	0.026		
269/1	0.032		
179/2	0.026		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-साराडीह बैराज निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़  
एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 12 नवम्बर 2014

क्रमांक/7984/भू-अर्जन/2014—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-अम्बागढ़ चौकी

(ग) नगर/ग्राम-बरारमुण्डी, प.ह.नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.403 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
16	0.036
17	0.036
27/1	0.170
27/2	0.161
योग	4
	0.403

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नांदिया-बरारमुण्डी मार्ग पर स्थित शिवनाथ नदी पर उच्चस्तरीय पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 12 नवम्बर 2014

क्रमांक/7985/भू-अर्जन/2014—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुन-व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मुरमुन्दा, प.ह.नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.145 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
866	0.145
योग	0.145

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-निर्माणाधीन मुरमुन्दा एनीकट कम काजवे हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 12 नवम्बर 2014

क्रमांक/7986/भू-अर्जन/2014—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुन-व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-नागतराई, प.ह.नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.162 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
125/1	0.012
129	0.061
128	0.040
130	0.049
योग	4
	0.162

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला एनीकट के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 12 नवम्बर 2014

क्रमांक/7987/भू-अर्जन/2014—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गाजमरा, प.ह.नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.134 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
172	0.134
योग	1 0.134

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डोंगरगढ़-चिचोला मार्ग के कि.मी. 13/10 पर गाजमरा नाला पर उच्चस्तरीय पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 12 नवम्बर 2014

क्रमांक/7988/भू-अर्जन/2014—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-घुसेरा, प.ह.नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.045 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
673/1	0.045
योग	1 0.045

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जटकन्हार-हरनसिंधी मार्ग पर पेटेश्री नदी पर उच्च स्तरीय पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर (छ.ग.)

अंबिकापुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2014

क्रमांक 4024/सामान्य/451/2014.-- श्री मनोज सिंह, पार्षद, इंदिरा गांधी वार्ड क्रमांक 14 सामान्य सभा की बैठक दिनांक 19-06-2013, 04-09-2013 एवं 15-01-2014 में लगातार बिना सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण आयुक्त, नगर पालिक निगम, अंबिकापुर द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 215/सचिव/न.पा.नि./2014 दिनांक 28-02-2014 द्वारा नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 17(2) के अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रस्तावित किया गया.

कलेक्टर सरगुजा के पत्र क्रमांक 5526/वलि/2014 अम्बिकापुर दिनांक 30-07-2014 अनुसार आयुक्त, नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर के प्रतिवेदन क्रमांक/722/न.पा.नि./सचिव/2014 दिनांक 07-07-2014 से सहमत होकर छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 में विहित प्रावधान के अधीन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किया है।

श्री मनोज सिंह, पार्षद, इन्दिरा गांधी वार्ड क्रमांक 14, नगर पालिक निगम अम्बिकापुर को अपना पक्ष रखने के लिए दिनांक 27-10-2014 दिन सोमवार को अपरान्ह 3.00 बजे का समय दिया गया था। श्री सिंह को कारण बताओ सूचना तामीली पश्चात् भी वे निर्धारित दिनांक 27-10-2014 को न्यायालयीन समय में उपस्थित नहीं हुए, अतः उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी।

आयुक्त, नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर एवं कलेक्टर सरगुजा के प्रतिवेदन के सहमत होते हुए मैं टी. सी. महावर, आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 19 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 17(2) सी का श्री सिंह द्वारा उल्लंघन पाए जाने के कारण श्री मनोज सिंह, पार्षद, इन्दिरा गांधी वार्ड क्रमांक 14 को पार्षद के पद से बर्खास्त करता हूँ।

टी. सी. महावर,  
आयुक्त.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 30th October 2014

No. 1217/Confdl./2014/II-3-14/2000 (Pt.-II).—On the application of Shri Jaideep, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Additional District & Sessions Judge, Uttar Bastar (Kanker), he is hereby, permitted to change his name as “Jaideep Garg” in place of “Jaideep”. It is directed that necessary changes be affected in all his records.

By the order of Hon'ble Acting Chief Justice,  
ASHOK PANDA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2014

क्रमांक 196/दो-2-39/2004.—श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर दिनांक 30-09-2014 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में, प्रदान की जाती है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
अशोक कुमार पण्डा, रजिस्ट्रार जनरल.